झारखण्ड सरकार

श्री रघुवर दास
माननीय मुख्यमंत्री

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

(झारखण्ड सरकार का पहला ISO 9001 : 2015 प्रमाणित विभाग)

वार्षिक कार्य प्रतिवेदन 2017 -18
एवं
वार्षिक कार्य योजना 2018 - 19

बदलता झारखण्ड

झारखण्ड सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

वार्षिक कार्य प्रतिवेदन
2017 – 18

एवं

वार्षिक कार्य योजना
2018 – 19

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

राज्य की जनता को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं से विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए अवगत कराना तथा जनता की समस्याओं एवं क्रिया-प्रतिक्रिया से सरकार को अवगत कराना सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का मुख्य दायित्व है। राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को संचार के विभिन्न माध्यमों यथा प्रेस, प्रकाशन, प्रदर्शनी, होर्डिंग, विज्ञापन आदि के साथ-साथ न्यू एज मीडिया के माध्यम से विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाता है। लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ प्रेस को मजबूत बनाने के लिए राज्य के पत्रकारों के कल्याणार्थ प्रेस क्लब भवन की स्थापना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना विभाग द्वारा लागू की गई है। वस्तुतः यह विभाग सरकार एवं जनता के बीच सेतु का कार्य करता है। यह सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराकर जन-जागरूकता उत्पन्न करता है तथा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं पुनर्गठन हेतु फीडबैक प्राप्त करता है। राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं को संचार के माध्यम से देश-विदेश में पहुँचा कर इस विभाग ने राज्य का मान भी बढ़ाया है।

वर्ष 2017-18 में विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ

- राज्य की आम जनता एवं सरकार के बीच बेहतर समन्वय एवं सीधा संवाद कायम करने के उद्देश्य से स्थापित "मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र" के माध्यम से आम जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास जगाने में सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र में प्राप्त आवेदनों पर प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को मुख्यमंत्री के सचिव द्वारा एवं प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्याओं के समाधान हेतु सीधी बात कार्यक्रम का आयोजन कर समस्याओं का समाधान किया जाता है। साथ ही राज्य की जनता से मिल रहे सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं को अमल में भी लाया जाता है, जिसके कारण आम जनता और राज्य सरकार के बीच एक बेहतर संवाद स्थापित हुआ है। अब तक कुल 5,06,440 लोगों से प्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क साधा गया है। कुल पंजीकृत मामले 1,72,541 है, जिसमें से 1,47,187 मामले संबंधित जिलों एवं विभागों को अग्रसारित किया गया है। 25,354 मामले जनसंवाद स्तर पर विलोपित किया गया है। अब तक 1,26,583 मामलों का संतोषजनक निष्पादन किया गया है।
- राज्य में फिल्म क्षेत्र में युवाओं की दिलचस्पी को देखते हुए एवं राज्य में फिल्म उद्योग की बढ़ती संभावनाओं को ध्यान में रखकर झारखण्ड फिल्म नीति- 2015 बनायी गई है, जिससे राज्य में फिल्मों के माध्यम से एक बेहतर संभावनाओं का उदय हुआ है। इस नीति के अंतर्गत कुल 04 बड़े बैनर की फिल्मों (बेगम जान, ए डेथ इन द गंज, अजब सिंह की गजब कहानी एवं रांची डायरी) को अनुदान दिया जा चुका है। इसके अलावा स्थानीय भाषाओं में बनी फिल्में यथा नाचे नागिन गली-गली (भोजपुरी), रोफा (संथाली), रूपेन्द्र गांधी -2 (पंजाबी) एवं काशी अमरनाथ (भोजपुरी) आदि फिल्मों को कुल अनुदान का 25 प्रतिशत दिया जा चुका है। इस नीति के द्वारा फिल्म उद्योग के नामचीन निदेशक एवं कलाकारों का ध्यान झारखण्ड की ओर

खींचने में सरकार को सफलता मिली है।

- लोकतंत्र के चतुर्थ स्तम्भ मीडिया एवं पत्रकारों के कल्याण हेतु भी सरकार कृतसंकल्प है, जिसका उदाहरण अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रांची प्रेस क्लब भवन बन कर तैयार है एवं इसका उद्घाटन किया जा चुका है। देवघर तथा धनबाद में प्रेस क्लब निर्माण प्रारंभ हो चुका है, साथ ही अगले वित्तीय वर्ष में पलामू एवं पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) जिले में भी भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाना है, जिस हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इन भवनों से राज्य ही नहीं, बल्कि देश के पत्रकार लाभान्वित होंगे।
- साथ ही सरकार के द्वारा झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना- 2016 को प्रभाव में लाया जा चुका है। इस योजना के तहत् कुल 2600.00 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदकों को बीमा का लाभ देने हेतु बीमा एजेंसी का चयन ई. टेंडर के माध्यम से करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।
- सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु राज्य के 24 जिलों में 32 एल.ई.डी. युक्त हाईड्रोलिक चलन्त वाहनों का परिचालन किया जा रहा है, जिनके द्वारा प्रखण्डों के अंतर्गत अवस्थित हाट-बाजारों में सरकार के योजनाओं से संबंधित जानकारी दी जा रही है। साथ ही रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, लातेहार, डाल्टनगंज, गुमला, सिमडेगा एवं गढ़वा में स्थापित फिक्सड एल.ई.डी. के माध्यम से सरकार की योजनाओं एवं सरकार द्वारा किये गये कार्यों की सूचना जनता तक पहुँचायी जा रही है। 13 जिलों के चयनित स्थलों पर फिक्स एल.ई.डी. लगाने की कार्रवाई की जा रही है। संचार के आधुनिक माध्यमों के उपयोग कर सरकार की आम जनता से जुड़ाव को मजबूती प्रदान करने में सफलता प्राप्त हुई है।
- सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में रांची विश्वविद्यालय एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के समन्वय से "खांची रेडिया" नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की जा रही है जिसके माध्यम से ग्रामीण जनता को लोक भाषा में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में इसी प्रकार के सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है।
- राज्य की महत्वपूर्ण विशिष्टताएं, सांस्कृतिक वैभव और उद्योग पर आधारित वृत्तचित्र का निर्माण व राष्ट्रीय चैनलों पर उसका प्रसारण।
- राज्य के विशिष्ट आध्यात्मिक स्थलों जैसे वैद्यनाथधाम, वासुकीनाथ, ईटखोरी, रजरप्पा में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए किये जा रहे सरकार द्वारा ठोस प्रयासों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने का कार्य, जिसका फायदा तीर्थयात्री व पर्यटक उठा रहे हैं।
- विभिन्न विभागों में हो रहे विकासात्मक कार्य का लघु फिल्मों, टीवीसी और रेडियो जिंगल द्वारा बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार किया गया है, जिसका लाभ आम जनता उठा रही है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में गैर योजना मद में बजट उपबंध

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए स्थापना व्यय मद में मुख्य शीर्ष 2251 सचिवालय समाजिक सेवाएँ तथा मुख्य शीष 2220 सूचना तथा प्रचार के अंतर्गत क्रमशः 1,27,61,000/-(एक करोड़ सताईस लाख एकसठ हजार) तथा 1,01,35,14,000/-(एक अरब एक करोड़ पैंतीस लाख चौदह हजार) रुपये का उपबंध निम्न प्रकार से प्राप्त है:-

क्रम सं.	मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष	बजट उपबंध (रुपये)
1.	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएँ-090- सचिवालय-15- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	1,27,61,000
2.	2220- सूचना तथा प्रचार-01- फिल्म -001 निदेशन और प्रशासन -01- निदेशन एवं प्रशासन	12,22,55,000
3.	2220- सूचना तथा प्रचार-01- फिल्म -001 निदेशन और प्रशासन -02- पत्रकार कल्याण कोष	15,00,000
4.	101- विज्ञापन और दृश्य प्रचार-02- सरकारी विज्ञापन	78,76,81,000
5.	106- क्षेत्र प्रचार -02- जिला भ्रमणशील इकाइयाँ	10,20,78,000
	कुल :	**1,02,62,75,000**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रस्तावित बजट उपबंध

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्थापना व्यय के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2251 सचिवालय समाजिक सेवाएँ तथा मुख्य शीष 2220 सूचना तथा प्रचार में क्रमशः 1,73,57,000/-(एक करोड़ तिहत्तर लाख सन्तावन हजार) तथा 96,06,60,000/-(छियानबे करोड़ छः लाख साठ हजार) रुपये का उपबंध निम्न प्रकार किया गया है:-

क्रम सं.	मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष	बजट उपबंध (रुपये)
1.	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएँ -090- सचिवालय -15- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	1,73,57,000
2.	2220- सूचना तथा प्रचार -01- फिल्म -001 निदेशन और प्रशासन -01- निदेशन एवं प्रशासन	6,66,65,000
3.	2220- सूचना तथा प्रचार -01- फिल्म -001 निदेशन और प्रशासन -02- पत्रकार कल्याण कोष	15,00,000
4.	101- विज्ञापन और दृश्य प्रचार -02- सरकारी विज्ञापन	80,00,00,000
5.	106- क्षेत्र प्रचार -02- जिला भ्रमणशील इकाइयाँ	9,24,95,000
	कुल :	**97,80,17,000**

वित्तीय वर्ष – 2017–18 में राज्य योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध

चालू योजना

योजना उद्व्यय 11526.97 लाख

(रुपये लाख में)

क्रम स.	योजना का नाम	कुल बजट उपबंध	जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना	अन्य क्षेत्रीय उपयोजना
1	फ्लैक्स, होर्डिंग, पुस्तिका (पम्पलेट्स) का निर्माण एवं प्रकाशन तथा साहित्य, मैगजीन, पोस्टर, विवरणिका, सजावटी विज्ञापन आदि का प्रकाशन	4550.97	2650.97	1900.00
2	फिल्म, वृत्तचित्र, विकास केन्द्रित सूचना पर विज्ञापनों का निर्माण तथा इलेक्ट्रॉनिक चैनलों द्वारा प्रसारण	3241.00	2641.00	600.00
3	मेला, प्रदर्शनी एवं विशेष प्रचार अभियान	200.00	120.00	80.00
4	सेमिनार, सिम्पोजियम, कॉन्फ्रेंस तथा कार्यशाला	85.00	65.00	20.00
5	गीत- नाट्य	160.00	100.00	60.00
6	सूचना भवन का अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण	100.00	70.00	30.00
7	विभागीय सूचना केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं नेटवर्किंग	140.00	140.00	0.00
8	जनसंचार उपकरणों का क्रय	60.00	35.00	25.00
9	प्रेस क्लब की स्थापना	730.00	230.00	500.00
10	सूचना भवन का निर्माण - मुख्य निर्माण कार्य	80.00	70.00	10.00
11	झारखण्ड फिल्म विकास निगम की स्थापना एवं फिल्म निर्माताओं हेतु वित्तीय सहायता	500.00	500.00	0.00
12	पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना	80.00	80.00	0.00
13	सरकारी कार्यक्रमों हेतु एल.ई.डी. वाहन	1020.00	720.00	300.00
14	सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम	90.00	90.00	**0.00**
15	सरकारी कार्यक्रमों हेतु बाह्य श्रोत से वाहन (ओ.बी.वैन)	490.00	490.00	**0.00**
	कुल :	**11526.97**	**8001.97**	**3525.00**

वित्तीय वर्ष – 2018–19 में राज्य योजना मद में प्रस्तावित बजट उपबंध

चालू योजना

योजना उद्व्यय 7000 लाख

(रुपये लाख में)

क्रम स.	योजना का नाम	कुल बजट उपबंध	जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना	अन्य क्षेत्रीय उपयोजना
1	फ्लैक्स, होर्डिंग, पुस्तिका (पम्पलेट्स) का निर्माण एवं प्रकाशन तथा साहित्य, मैगजीन, पोस्टर, विवरणिका, सजावटी विज्ञापन आदि का प्रकाशन	1600.00	1000.00	600.00
2	फिल्म, वृत्तचित्र, विकास केन्द्रित सूचना पर विज्ञापनों का निर्माण तथा इलेक्ट्रॉनिक चैनलों द्वारा प्रसारण	900.00	800.00	100.00
3	मेला, प्रदर्शनी एवं विशेष प्रचार अभियान	240.00	140.00	100.00
4	सेमिनार, सिम्पोजियम, कॉन्फ्रेंस तथा कार्यशाला	60.00	35.00	25.00
5	गीत- नाट्य	170.00	100.00	70.00
6	सूचना भवन का अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण	100.00	60.00	40.00
7	विभागीय सूचना केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं नेटवर्किंग	400.00	400.00	0.00
8	जनसंचार उपकरणों का क्रय	80.00	50.00	30.00
9	प्रेस क्लब की स्थापना	1100.00	100.00	1000.00
10	सूचना भवन का निर्माण - मुख्य निर्माण कार्य	110.00	100.00	10.00
11	झारखण्ड फिल्म विकास निगम की स्थापना एवं फिल्म निर्माताओं हेतु वित्तीय सहायता	500.00	500.00	0.00
12	पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना	50.00	50.00	0.00
13	सरकारी कार्यक्रमों हेतु एल.इ.डी. वाहन	1000.00	600.00	400.00
14	सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम	90.00	90.00	0.00
15	मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र का संचालन एवं क्रियान्वयन (नई योजना)	600.00	600.00	0.00
	कुल	**7000.00**	**4625.00**	**2375.00**

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की वित्तीय वर्ष 2018–19 की कार्य योजना

1. **फ्लैक्स, होर्डिंग, पुस्तिका (पम्पलेट्स) का निर्माण एवं प्रकाशन तथा साहित्य, मैगजीन, पोस्टर, विवरणिका, सजावटी विज्ञापन आदि का प्रकाशन :-** वित्तीय वर्ष 2018-19 में सरकार की उपलब्धियों, कार्यक्रमों एवं नीतियों का राज्य के आम लोगों तक प्रचार-प्रसार हेतु नई होर्डिंग्स संरचना स्थापित करने, अति महत्त्वपूर्ण स्थानों पर L.E.D. स्क्रीन की संस्थापना एवं अनुरक्षण, सजावटी विज्ञापन (Display Advertisement) तथा मुख्यालय सहित विभिन्न जिलों में अवस्थित क्षेत्रीय इकाईयों के लिए आधिकारिक डायरी, कैलेण्डर, पत्रिका विवरणी के प्रकाशन की योजना प्रस्तावित है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 1600.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 1000.00 लाख तथा अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 600.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

2. **फिल्म, वृत्तचित्र, विकास केन्द्रित सूचना पर विज्ञापनों का निर्माण तथा इलेक्ट्रॉनिक चैनलों द्वारा प्रसारण :-** राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं नीतियों के संबंध में दृश्य-श्रव्य विज्ञापन (टी.वी.स्पॉट), कल्याणकारी उपायों पर आधारित वृत्त चित्र और सरकारी योजनाओं पर आधारित विज्ञापनों का निर्माण कर उन्हें दूरदर्शन, आकाशवाणी, निजी इलेक्ट्रॉनिक, सेटेलाइट चैनल, एफ.एम. रेडियो, टी.वी. इत्यादि के माध्यम से प्रसारण की योजना है। साथ ही न्यू एज मीडिया यथा फेसबुक, लिंक्ड-इन, यू-ट्यूब ट्विटर, प्रोजेक्शन मैपिंग, मोबाइल स्कैनिंग, जियो लोकेशन सर्विस इत्यादि के माध्यम से सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार की योजना है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 900.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 800.00 लाख तथा अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के तहत 100.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

3. **मेला, प्रदर्शनी एवं विशेष प्रचार अभियान :-** इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यों के प्रति आम जन में जागरूकता फैलाना है। इसके तहत् राज्य के क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों के द्वारा विशेष अवसरों यथा-राष्ट्रीय समारोहों, श्रावणी मेला, हिजला मेला, जगन्नाथपुर रथ यात्रा मेला आदि के अवसर पर प्रदर्शनी शिविर के माध्यम से प्रचार-प्रसार किए जाने की योजना है। साथ ही गणतंत्र दिवस एवं अन्य महत्त्वपूर्ण अवसरों पर झांकी के माध्यम से राज्य की कला-संस्कृति, महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों आदि का प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली में स्टॉल लगाना इत्यादि योजनाएँ भी प्रस्तावित है। इस

योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 240.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 140.00 लाख तथा अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 100.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

4. **विभागीय सूचना केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं नेटवर्किंग :-** सरकारी योजनाओं/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से मुख्यालय सहित राज्य के सभी जिलों से ऑनलाइन विज्ञापन एवं प्रेस विज्ञप्ति प्राप्त किया जा रहा है एवं प्रेषित भी किया जा रहा है। इस इकाई के अन्तर्गत सूचना एवं जनसंचार की नवीनतम तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। सूचना के सम्प्रेषण, ऑनलाइन विज्ञापन निर्गम, इंटरनेट लीजलाइन का अनुप्रयोग, विभागीय वेबसाइट का रख-रखाव, मुख्यमंत्री-वेबसाइट का प्रबंधन तथा SMS एकीकरण एवं संबंधित उपकरणों का क्रय इस योजना के अपरिहार्य भाग है।

साथ ही समाचार-पत्रों के महत्त्वपूर्ण कतरन ऑनलाइन ई-मेल के माध्यम से राज्य मुख्यालय से लेकर जिला तक संप्रेषित किये जा रहे हैं। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के नियमों/अधिसूचना/अनुदेश/नीतियों को संकलित कर ऑनलाइन किया गया है। साथ ही, विभिन्न विभागों से प्राप्त विज्ञापनों के प्रकाशन के उपरांत प्रकाशित सामग्रियों को ई-मेल पर सुलभ कराया जा रहा है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 400.00 लाख रुपये प्रस्तावित हैं, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 400.00 लाख रूपये मात्र प्रस्तावित है।

5. **सेमिनार-सिम्पोजियम, कॉन्फ्रेंस एवं वर्कशॉप :-** सूचना एवं जनसम्पर्क से संबंधित नियमित क्षमता संवर्द्धन हेतु जनसंचार एवं विकास से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों/संस्थानों के सहयोग से एवं उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों, मीडिया प्रोफेशनल्स, जनसंचार के विद्यार्थियों एवं अन्य संबंधितों के लिए विभाग द्वारा राज्य एवं राज्य के बाहर (मुख्यालय राँची सहित राज्य के पाँच प्रमण्डल मुख्यालयों तथा दिल्ली सहित देश के अन्य प्रमुख स्थानों में) सेमिनार-सिम्पोजियम, वर्कशॉप, कंडक्टेड टूर के कार्यक्रम एवं विभिन्न विषयों पर समय-समय पर सेमिनार एवं संगोष्ठी आदि आयोजित करने का प्रस्ताव है।

साथ ही सरकार द्वारा चलाये जा रहे विकास एवं कल्याणपरक कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा समीक्षा एवं अध्ययन हेतु शोध एवं अन्वेषण योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारंभ है। सरकार की विभिन्न नीतियों, विकासोन्मुखी एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित शोध एवं अन्वेषण हेतु संदर्भ सामग्रियों का संकलन-प्रकाशन एवं विशिष्ट अकादमिक संस्थाओं के द्वारा मूल्याकंन एवं अध्ययन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस हेतु संबंधित क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान अथवा अनुभव-प्राप्त व्यक्तियों/संस्थाओं को संस्थागत फेलोशिप दिये जाने का भी प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त झारखण्ड के सभी वर्गों के छात्र जो कि देश के नामी संस्थानों से जन-संचार की पढ़ाई करने के इच्छुक हैं उन्हें पाठन-शुल्क (ट्यूशन फीस) के रूप में 100 प्रतिशत सहायता अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। यह सहायता केवल IIMC नई दिल्ली एवं धेनकनाल, जामिया मिलिया, नई दिल्ली, फिल्म एवं टेलिविजन संस्थान-पुणे, सत्यजीत रे फिल्म संस्थान, कोलकाता तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए मान्य होगी।

इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 60.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 35.00 लाख तथा अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के तहत 25.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

6. **गीत नाट्य :-** यह प्रचार-प्रसार का एक अत्यंत सुदृढ़, सशक्त एवं प्रभावपूर्ण माध्यम है। गीत-नाट्य में स्थानीय कलाकारों एवं स्थानीय लोक गीतों का प्रयोग किया जाता है, जिस वजह से स्थानीय लोग आसानी से जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। इस योजना के तहत् मुख्यालय सहित राज्य के सभी जिलों में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं विकास कार्यक्रमों का पारम्परिक प्रचार माध्यमों से स्थानीय लोक दलों एवं लोक भाषा के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाता है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 170.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 100.00 लाख तथा अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के तहत 70.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

7. **सूचना भवन का अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण :-** राँची स्थित सूचना भवन एवं कतिपय अन्य क्षेत्रीय इकाइयों के सूचना भवनों के अनुरक्षण, मरम्मति, बाहरी दीवारों का निर्माण एवं आंतरिक सुसज्जीकरण हेतु योजना प्रस्तावित है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 100.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 60.00 लाख तथा अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 40.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

8. **जनसंचार उपकरणों का क्रय :-** जनसंचार, विभाग का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कार्य है। अतएव विभाग के विभिन्न कार्यालयों में सम्प्रेषण उपकरणों की उपलब्धता अवश्यम्भावी है। टी.वी. सेट, जन-संबोधन उपकरण व्यवस्था, LED, कम्प्यूटर सेट इत्यादि का क्रय एवं विभाग से संबंधित महत्त्वपूर्ण सभागार कक्षों में पी.ए. सिस्टम का अधिष्ठापन के लिए किया जाना प्रस्तावित है। इन उपकरणों को जिला, प्रखण्ड, मुख्यालय तथा विभाग के दिल्ली स्थित कार्यालयों में प्रस्थापित किया जाएगा। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 80.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 50.00 लाख तथा अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 30.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

9. **प्रेस क्लब की स्थापना :-** लोकतंत्र के चतुर्थ स्तम्भ मीडिया एवं पत्रकारों के कल्याण हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रांची प्रेस क्लब भवन बन कर तैयार है एवं इसका उद्घाटन किया जा चुका है। देवघर तथा धनबाद में प्रेस क्लब निर्माण प्रारंभ हो चुका है, साथ ही अगले वित्तीय वर्ष में पलामू एवं पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) जिले में भी भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाना है, जिस हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 1100.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपये मात्र एवं अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 1000.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

10. **सूचना भवन निर्माण - मुख्य निर्माण कार्य :-** वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्माणाधीन सूचना भवनों हेतु राशि उपबंध किये जाने हेतु राशि का उपबंध किया जा रहा है। सिमडेगा जिला में भी सूचना भवन के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 110.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 100.00 लाख तथा अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 10.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

11. **झारखण्ड फिल्म विकास निगम की स्थापना एवं फिल्म निर्माताओं हेतु वित्तीय सहायता :-** झारखण्ड सरकार के द्वारा झारखण्ड फिल्म नीति 2015 का गठन किया गया है। इस नीति के अंतर्गत राज्य में फिल्म स्टूडियोज, फिल्म सिटी, थियेटर एवं मल्टीप्लेक्स की स्थापना हेतु निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। विभाग के द्वारा फिल्म विकास निधि के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। इस फिल्म नीति में थियेटरों का पुनरूद्धार एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर थियेटरों के लिए भूमि उपलब्ध कराना भी शामिल है। साथ ही फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, तकनीकी विशेषज्ञों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत झारखण्ड फिल्म विकास निगम की स्थापना एवं राज्य में प्रत्येक वर्ष फिल्म महोत्सव का आयोजन भी प्रस्तावित है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 500.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 500.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

12. **सरकारी कार्यक्रमों के लिए एल.इ.डी. वैन :-** सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु राज्य के 24 जिलों में 32 एल.ई.डी. युक्त हाईड्रोलिक चलन्त वाहनों का परिचालन किया जा रहा है, जिनके द्वारा प्रखण्डों के अंतर्गत अवस्थित हाट-बाजारों में सरकार के योजनाओं से संबंधित जानकारी दी जा रही है। इन वाहनों में जी.पी.एस. की सुविधा होती है ताकि विभाग के द्वारा मुख्यालय स्तर पर इसका अनुश्रवण किया जा सके। भविष्य में

इन वाहनों के माध्यम से सीधा प्रसारण भी कराया जायेगा ताकि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार एवं आमजन के बीच सीधी वार्त्ता संभव हो सके। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 1000.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 600.00 लाख रुपये मात्र एवं अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 400.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

13. **पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना :-** राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से राज्य के पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की घोषणा की गई, एवं इस योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन भी प्राप्त कर ली गई है। इस योजना के तहत् कुल 2600.00 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदकों को बीमा का लाभ देने हेतु बीमा एजेंसी का चयन ई. टेंडर के माध्यम से करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 50.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 50.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

14. **सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम :-** सरकार के जन-कल्याणकारी योजनाओं एवं जन-समस्याओं के समाधान संबंधी सुझावों को रेडियो के माध्यम से श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग एवं रांची विश्वविद्यालय के समन्वय से खांची रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई है। अगले वित्तीय वर्ष में अन्य सरकारी विश्वविद्यालयों में भी ऐसे ही सामुदायिक रेडियो स्टेशन के स्थापना की योजना है। इन स्टेशनों में इले. इंजीनियर, प्रोग्राम कम्पोजर, रेडियो जॉकी कार्यरत किये जायेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में श्रोताओं हेतु रेडियो वितरण भी किया जायेगा। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 90.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 90.00 लाख रूपये मात्र प्रस्तावित है।

15. **मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र का संचालन एवं क्रियान्वयन :-** वित्तीय वर्ष 2018-19 से नई योजना प्रारम्भ की जा रही है। राज्य की आम जनता एवं सरकार के बीच बेहतर समन्वय एवं सीधा संवाद कायम करने के उद्देश्य से वर्ष- 2015 में "मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र" की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र में प्राप्त आवेदनों पर प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को मुख्यमंत्री के सचिव द्वारा एवं प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री जी द्व ारा समस्याओं के समाधान हेतु सीधी बात कार्यक्रम का आयोजन कर समस्याओं का समाधान किया जाता है। साथ ही राज्य की जनता से मिल रहे सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं को अमल में भी लाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र के संचालन एवं क्रियान्वयन पर होने वाले समस्त प्रकार के व्यय शामिल होंगे। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 600.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 600.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

191/01/18• kailashpaper.org • 92631 80313 / 14 / 15